13 हवाई अड्डों का निजीकरण होगा

योजना

नई दिल्ली | एजेंसी

सरकार की योजना वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की है।

एएआई के अध्यक्ष संजीव कुमार ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, हमने विमानन मंत्रालय को 13 हवाई अड्डों की सूची भेजी है, जिन्हें पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पर बोली लगाई जानी है। योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इन हवाई अड्डों की बोली को पूरा करने की है। उन्होंने कहा, बोली लगाने के लिए जिस मॉडल का पालन किया जाएगा वह प्रति यात्री राजस्व मॉडल होगा। यह मॉडल पहले इस्तेमाल किया जा चुका है और सफल रहा है और जेवर हवाई अड्डे के लिए भी उसी मॉडल पर बोली लगाई गई थी।

सात छोटे हवाईअड्डों संग छह बड़े मिलाए जाएंगे

एएआई ने सात छोटे हवाई अड्डों को छह बड़े हवाई अड्डों के साथ मिलाने का फैसला किया है – कुशीनगर और गया के साथ वाराणसी; कांगड़ा के साथ अमृतसर; तिरुपति के साथ भुवनेश्वर; औरंगाबाद के साथ रायपुर; जबलपुर के साथ इंदौर; और हुबली के साथ त्रिची। एएआई अब नए हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार की योजना अगले चार वर्षों में 25 हवाई अड्डों को प्रदान करने की है, जिसमें ये 13 भी शामिल हैं। यह 2019 में निजीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत में अदानी समूह को दिए गए छह हवाई अड्डों के क्रम में हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों को निजी ऑपरेटरों को सौंपा जा चुका है।